

न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, श्रीगंगानगर

पीठासीन अधिकारी श्री प्रेमराम परमार, आर.ए.एस.

अपील संख्या 08/2017

1. जगदीश चन्द पुत्र सुलतानराम जाति जाट निवासी मदेरा तहसील व जिला श्रीगंगानगर ।
2. दिनांद कुमार पुत्र सुलतानराम जाति जाट निवासी मदेरा तहसील व जिला श्रीगंगानगर — अपीलार्थीगण

बनाम

1. मन्नीदेवी पत्नी रणजीतसिंह पुत्र हरचन्द जाति जाट निवासी ख्योवाली तहसील सिरसा हरियाणा ।
2. कुलवंतसिंह } पिसरान रणजीत जाति जाट निवासी ख्योवाली
3. हनुमान } तहसील सिरसा हरियाणा
4. नरेश कुमार }
5. विद्यादेवी पत्नी आत्माराम पुत्र हरचन्द जाति जाट निवासी ख्योवाली तहसील सिरसा हरियाणा
6. राजेन्द्र कुमार पुत्र आत्माराम पुत्र हरचन्द जाति जाट निवासी ख्योवाली तहसील सिरसा हरियाणा
7. कृष्णादेवी पुत्री आत्माराम पुत्र हरचन्द जाति जाट निवासी ख्योवाली तहसील सिरसा हरियाणा
8. स्टेट आफ़ राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार श्रीगंगानगर।

—रेसॉडेंट

अपील अन्तर्गत धारा 223 रा.का.अ. 1955


विरुद्ध आदेश सहायक कलेक्टर (फारट ट्रेक) श्रीगंगानगर दिनांक 18.01.2017
उपरिस्थिति:-

श्री ओमप्रकाश बतरा, अभिभाषक अपीलार्थी
श्री दिनेश छाबड़ा अभिभाषक ~~रखते~~
श्री इकबाल सिंह सिद्धू, राजकीय अधिवक्ता

निर्णय

दिनांक - 20.11.2017

प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं वादीगण/अपीलार्थीगण ने एक वाद न्यायालय उपखंड अधिकारी श्रीगंगानगर के समक्ष रा.का.अ. की धारा 88.91



20/11/17
राजस्व अपील प्राधिकारी
श्रीगंगानगर (राज.)

का पेश कर निवेदन किया कि एक 7 डी बड़ी के खाता सं. 51/50 मु.न. 25 के कि.न. 2 से 15 की 3.082 हे० तथा मु.न. 26 के कि.न. 1/1 की 0.126 हे० व 57/9 का 0.076 हे. कुल 3.264 हे० का पूर्व में वादीगण के पूर्वजों के पास अब वादीगण के कब्जा काल में पिछले 30 साल से चला आ रहा है। वादीगण प्रतिकूल कब्जा के आधार पर इस भूमि के खातेदार हो चुके हैं। अतः निवेदन है कि वादीगण को उक्त भूमि का खातेदार घोषित किया जावे। प्रतिवादीगण ने जबाब दावा पेश कर कथन किया कि विवादित भूमि पर वादीगण का कब्जा प्रतिकूल न होकर प्रतिवादीगण की सहमति से कब्जा है। ऐसी स्थिति में वादीगण का वाद स्वीकार किये जाने योग्य नहीं होने से अस्वीकार किया जावे।

दावा एवं जबाब दावा के आधार पर अनुतोष सहित 8 वाद बिन्दु कायम किये गये। सुनवाई करने के पश्चात् अधी. न्यायालय द्वारा दिनांक 16.01.2017 को वाद खारिज कर दिया। जिसके विरुद्ध वादीगण/अपीलार्थीगण ने यह अपील पेश की है।

विद्वान अभिभाषक अपीलार्थीगण ने अपनी बहस में मुख्य रूप से वाद पत्र एवं अपील नोटों में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि विवादित भूमि पर पहले वादीगण के पूर्वजों का एवं वर्तमान में वादीगण का कब्जा पिछले 30 वर्षों से बिना किसी रुकावट के चला आ रहा है। प्रतिवादीगण ने कब्जा प्राप्त करने के लिए कोई कार्यवाही नहीं करने से उनके इस भूमि पर हक व अधिकार समाप्त हो चुके हैं। वादीगण ने अधी. न्यायालय में वाद पेश किया एवं साक्ष्य से अपने वाद को पूर्ण रूप से साबित किया था फिर भी अधी. न्यायालय ने वाद को खारिज कर दिया। अतः निवेदन है कि अपील अपीलाट स्वीकार कर अपीलापीन आदेश को निरस्त करते हुए वाद वादीगण स्वीकार किया जावे। अपने पक्ष के समर्थनमें वकील अपीलाट ने आरआरडी 1999 पेज 186, आरबीजे (14) 2007 पेज 821, आरआरडी 1996 पेज 288, आरआरडी 2007 पेज 915, आरआरडी 2009 पेज 252 आरआरटी 2007(2)पेज 1245, आरआरडी 1989 पेज 300 को नजीरे पेश की।

विद्वान अभिभाषक रेसपो. अपनी बहस में कथन किया कि विवादित भूमि पर वादीगण का कब्जा प्रतिवादीगण की सहमति से था। प्रतिकूल कब्जा के आधार पर खातेदारी अधिकार दिये जाने का कोई प्रावधान विधि में नहीं है। राजस्व


20/1/17
राजस्व अपील प्राधिकारी
श्रीगंगानगर (राज.)



रिकार्ड में विवादित भूमि प्रतिवादीगण के नाम से है। अधीन्यायालय ने प्रत्येक तनकी का विस्तृत विवेचन करते हुए वाद खारिज किया है जिसमें कोई त्रुटि नहीं है अतः अपील खारिज की जावे। अपने पक्ष के समर्थन में वकील रेष्यो ने 2011 आरबीजे पेज 508, 2016 आरबीजे पेज 340, 2015 आरबीजे पेज 648, 2016 आरबीजे पेज 904 की नजीरे पेश की। इसके अलावा वकील रेष्यो ने फॉस ऑब्जर्वेशन पेश कर तनकीयात का निर्णय प्रतिवादीगण के पक्ष में निर्णित करने का निवेदन किया।

उभय पक्ष की बहस पर मनन किया तथा पत्रावली का अवलोकन किया गया।

अपील अधीन्यायालय सहायक कलेक्टर (फास्ट ट्रैक) श्रीगंगानगर के निर्णय दिनांक 16.01.2017 के विरुद्ध पेश की है जिसमें अपीलान्त का प्रतिकूल कब्जे के आधार पर घोषणात्मक दावा खारिज किया। दावे में प्रतिकूल कब्जा साबित होने के बावजूद आराजी कृषि भूमि होने तथा काश्तकारी अधिनियम में प्रतिकूल कब्जे के प्रावधानों न होने की गलत ध्याख्या कर दावा गलत खारिज किया जिसे निरस्त करने का अनुतोष चाहा।

अधीन्यायालय की पत्रावली का अवलोकन किया। अधीन्यायालय द्वारा दावा एवं जबाब दावे के आधार पर मूल रूप से निम्नानुसार तीन तनकीयात कायम की थी :-

1. आया कि वादीगण के पास चक 7 डी बडी तहसील गंगानगर के खाता संख्या 51/50 के मुख्बा नम्बर 25 कि.न. 2 से 15 में 3.082 हेक्टर मु.न. 26 में कि.न. 1(0.126)80 एवं खाता संख्या 67/9 में 0.078 हेक्टर कुल 3.264 हेक्टर रकबा पर कब्जागत 30 वर्षों से चला आ रहा है। -वादीगण
 2. आया कि वादीगण कब्जा 30 साल होने से यादीगण को उपरोक्त जमीन की खातेदारी घोषित करवाने का हकदार है। -वादीगण
 3. आया कि वादीगण उपरोक्त भूमि पर अतिक्रमी होने के कारण खातेदारी अधिकार प्राप्त करने के अधिकारी नहीं है। - प्रतिवादीगण
- उपरोक्त तनकीयात में तनकी संख्या 1 व 2 वादीगण द्वारा साबित की जानी थी तथा तनकी संख्या 3 को साबित करने का भार प्रतिवादीगण के जिम्मे था। उपरोक्त तीनों तनकीयात में सिविल प्रक्रिया सहित के आदेश



[Handwritten Signature]
 20/11/17
 राजस्थान अपील प्राधिकारी
 श्रीगंगानगर (राज.)

-4-

14 नियम 1 के प्राधानुसार तनकी सं. 1 Issue of facts की है व तनकी सं. 2 व 3 Issue of law की है।

उपरोक्त तनकीयात कायम के पश्चात संशोधित तनकीयात बनी जिसमें 2 अतिरिक्त तनकीयात निम्नानुसार बनाई गईं

4. क्या प्रश्नगत कृषि भूमि प्रतिवादीगण के पूर्वजों की खातेदारी कृषि भूमि होने के कारण प्रतिवादीगण विरासततन प्राप्त कर राजस्व अभिलेखों में अपने नाम दर्ज करवाने के अधिकारी हैं। — प्रतिवादीगण

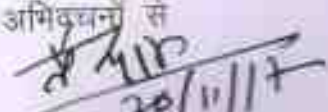
5. प्रश्नगत कृषि भूमि पर वादीगण का प्रतिकूल कब्जा नहीं बल्कि प्रतिवादीगण की सहमति से ही है। — प्रतिवादीगण

उपरोक्त दोनों तनकीयात में तनकी संख्या सं० 1 Issue of facts में साक्ष्य संग्रहित होकर वादी अपीलान्ट के पक्ष में अधीन न्यायालय द्वारा निम्नानुसार निर्णित की गई है।

आया कि वादीगण के पास चक 7 डी बड़ी तहसील मंगानगर के खाता संख्या 51/50 के मुरब्बा नम्बर 25 कि.न. 2 से 15 में 3.062 हेक्टर मु.न. 26 में कि.न. 1(0.126) है 0 एवं खाता संख्या 67/9 में 0.076 हेक्टर कुल 3.264 हेक्टर रकबा पर कब्जा गत 30 वर्षों से चला आ रहा है। — वादीगण


पत्रावली में प्रस्तुत अभिलेखानुसार प्रदर्श-4ए सिंचाई विभाग द्वारा जारी रसीद संख्या 412/45 दिनांक 02 जून 1983 से प्रदर्श 18 ए से यह तथ्य सिद्ध होता है कि वादीगण का चक 7 डी बड़ी तहसील के खाता संख्या 51/50 मुरब्बा नम्बर 25 कि.न. 2 से 15 कुल 3.062 है. मु.न. 28 कि.न. 1(0.126) एवं खाता संख्या 67/9 में 0.076 है. कुल 3.264 है 0 कृषि भूमि पर गत 30 वर्षों से कब्जा चला आ रहा है ऐसी स्थिति में विद्यावक संख्या वादीगण के पक्ष में में विनिश्चित किया जाता है।

तनकी संख्या 2 Issue of law में प्रतिवादी /रेसपो द्वारा एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत सिविल प्रक्रिया सहित आदेश 7 नियम 11 के तहत पेश कर Legal Issue अपीलान्ट के विरुद्ध निर्णित का दावा खारिज करने का अनुतोष चाहा । प्रार्थना पत्र की इबारत है कि " वादी की ओर से धारा 88, 92 ए राजस्थान कारतकारी अधिनियम के अन्तर्गत बरदिनाए मुखालफाना कब्जा के आधार पर खातेदारी प्राप्त करने हेतु प्रस्तुत किया है जो कि वाद पत्र के अभिव्यक्तों से


20/11/17
राजस्थान अपीलान्त अधिकारी
बीकानेर (राज.)

स्पष्ट है। यह कि राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की तृतीय अनुसूची में एवं धारा 88 के अन्तर्गत मुखालफाना (एडवर्स पोजेशन) के आधार पर खातेदारी दिये जाने का कोई प्रावधान नहीं है। इस सम्बन्ध में कानूनी प्रावधान स्पष्ट है। यह कि उपरोक्त वर्णित तथ्यों के आधार पर वादीगण को न तो कोई वाद हेतुक मौजूदा वाद प्रस्तुत करने का हासिल है एवं ना ही माननीय न्यायालय को वाद सुनने का क्षेत्राधिकार ही प्राप्त है इसलिए वाद आदेश 7 नियम 11 जाब्त दिवानी के प्रावधानों के अन्तर्गत निरस्त किये जाने योग्य है। यह कि प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्य कानूनी है जिन्हें माननीय न्यायालय स्वयं भी देखकर निर्णय करने में सक्षम है। रिफाये उज्र जबाबदावा पूर्व में ही प्रस्तुत किया जा चुका है एवं किसी भी प्रकार से साक्ष्य की आवश्यकता नहीं है। यह प्रा.पत्र अधी. न्यायालय द्वारा विभिन्न न्याय सिद्धांतों के विवेचन के साथ खारिज किया अर्थात यह तनकी वादीगण/अपीलांट के विरुद्ध प्रा.पत्र निस्तारण में निर्णित नहीं हुआ यद्य पक्ष में निर्णित हुई। सन्दर्भ अधी. न्यायालय का निर्णय दिनांक 08.11.2012 का Text है कि अधिवक्तागण उपस्थित। प्रतिवादीगण की ओर से आवेदन पत्र दिनांक 23 दिसम्बर, 2012 अन्तर्गत आदेश 7 नियम 11 व वाद प्रक्रिया संहिता प्रस्तुत किया गया कि राज.काश्त.अधि. की तृतीय अनुसूची में एवं अधि. की धारा 88 के अन्तर्गत विपरीत कब्जा (ADVERSE POSSESSION) के आधार पर खातेदारी दिये जाने का कोई प्रावधान नहीं है। वाद पत्र के तथ्यों के आधार पर वादीगण को किसी भी प्रकार का वाद हेतुक उपलब्ध नहीं है। अतिरिक्त, न्यायालय को वाद का क्षेत्राधिकार भी उपलब्ध नहीं है। ऐसी स्थिति में आदेश 7 नियम 11 व्य. प्र.सं. के अन्तर्गत वाद पत्र निरस्त किये जाने योग्य है। इस प्रकार की आपत्तियां जबाब पत्र में भी प्रस्तुत की गई हैं। इस प्रकार प्रतिवादीगण द्वारा वाद पत्र निरस्त किये जाने का निवेदन किया गया है। वादीगण द्वारा जबाब आवेदन पत्र दिनांक 04.07.2013 अन्तर्गत आदेश 7 नियम 11 व्य.प्र.सं. प्रस्तुत किया गया कि वाद पत्र में अंकित तथ्यों के अनुसार वाद पत्र माननीय न्यायालय के क्षेत्राधिकार से ही सम्बन्धित है। प्रकरण इस स्तर पर निरस्त नहीं किया जा सकता क्योंकि प्रतिवादीगण अपनी आपत्तियों को जबाब दावा में अंकित किया जा सकता है जिसके आधार पर विवाहकों का निर्धारण करने के उपसंत ही निर्णय पारित किया जा सकता है। अतः आवेदन पत्र अस्वीकार किये जाने का निवेदन किया।




 20/11/17
 राज्यस्व अपील प्राधिकारी
 भोगानगर (राज.)

अधिवक्तागण द्वारा प्रस्तुत बहस सुनी गई। पत्रावली में उपलब्ध तथ्यों को अवलोकन करते हुए प्रस्तुत बहस एवं न्यायिक दृष्टांत कमरा:

- * 2006-07 (Suppl.) RRT 421 SARJU (SMT.) & ORS. VS. HASTIMAL & ORS.
- 2012(2) DNJ (RAJ) 806 NANURAM SHARMA & ANR. VS. ADDL.DJ. & ORS.
- 2012(3) DNJ (RAJ) 1569 DEVI BAI (SMT.) VS. ADDL.C.J.# 1 & ORS.
- 2009(1) RRT 230 AMARSING VS. DEEPCHAND & ORS.
- 2011-12(SUPPLI.) RRT 74 BHAIRU & ANR VS. BOARD OF REVENUE & ORS.
- 2013(2) DNJ(RAJ.) 552 POONAMCHAND & ANR VS. PHOOLRAM

का सादर अवलोकन किया गया।

वादपत्र में विवाद्यक निर्धारित किये जा चुके हैं तथा वादपत्र साक्ष्य स्तर पर विचारार्थ है। प्रस्तुत होने वाले साक्ष्यों के आधार पर विपरीत कब्जा (ADVERSE POSSESSION) की बाबत विनिश्चय किया जा सकता है। इस प्रकार प्रस्तुत आवेदन पत्र आदेश 7 नियम 11 व्य.प्र.सं. के 8 प्राक्धानों के अन्तर्गत वाद पत्र निरस्त नहीं किये जाने योग्य पाया जाता है। अतः आवेदन पत्र अस्वीकार किया जाता है।" अधी. न्यायालय द्वारा निर्मित तनकीयात में दो तनकीयात तनकी सं. 1 व 2 ही दावे के निर्णय में पर्याप्त थी परन्तु अतिरिक्त व संशोधित तनकीयात इन दो तनकीयों की पूरक होने से तनकी सं. 1 निर्विवाद रूप से साक्ष्यों के आधार पर विवादित आराजी तहसील श्रीगंगानगर का चक 7धी बड़ी खाता सं. 51/50 मु.नं. 25 कि.नं. 2 से 15 की 3.082है०, मु.नं. 26 कि. नं. 1(0.126है) एवं खाता सं. 67/9 में 0.076है० कुल 3.264है० पर अपीलांत का तीस वर्षों से कब्जा चला आ रहा है साबित होने से अधी. न्यायालय द्वारा अपीलांत के पक्ष में निर्णित की है जिसके विवेचन में कोई त्रुटि नहीं है। रेष्यों अभिभाषक ने अपनी लिखित बहस में भी नहीं दर्शाई है तथा उभयपक्ष अभिभाषकगण की लिखित बहस एवं न्याय सिद्धांत तनकी सं. 2 के आस-पास सीमित है। अतः अपीलाधीन आदेश के Proper विधिक निर्णय हेतु सारभूत तनकी सं. 2 विस्तृत विवेचन योग्य है जिसके सम्बन्ध में अपीलांत अभिभाषक द्वारा अपनी लिखित बहस में जाहिर किया कि राज.कास्त.अधि. की 1955 की धारा 183 में कब्जा वापसी का दावा करने की मियाद 12 वर्ष है जो मियाद अधिनियम की धारा 27 के Corresponding है, लिखित बहस में मियाद का बिन्दु कास्त. अधि. की अनुसूची 3 के क.संख्या 23 पर होना जाहिर किया। सन्दर्भ कानूनी



(Signature)
 20/11/17
 राजस्व अपील अधिकारी
 श्रीगंगानगर (राज.)

प्रावधानों का अवलोकन किया जिसका Text of section 183 of Tenancy Act 1956 धारा 183 जिसमें कब्जा वापसी का दावा अनुसूचि 3 के क्रम सं. 23 के अनुसार 12 वर्ष तक पेश किया जा सकता है जो अपीलेंट के कथनानुसार विधिसम्मत है।

अपीलांट द्वारा अपनी लिखित बहस में जाहिर किया कि राज.काश्त.अधि. 1955 की धारा 214(3) द्वारा केन्द्रीय मियाद अधिनियम 1908 के प्रावधान काश्तकारी अधिनियम के लिये Adopt किये हैं जिसमें मियाद अधिनियम 1963 के प्रावधान समाहित है जिसके पार्ट- IV अनुसार अपीलांट को खातेदारी अधिकार प्राप्त हो चुके हैं। अपने कथन के समर्थन में न्याय सिद्धांत आर.आर.डी. 1999 पेमजी बनाम नाथुजी चगेरह अपील सं. 16/ इंगरपुर Of 97, निर्णय दिनांक 22.01.1999 पेश किया है जिसमें held किया है कि " Rajasthan Tenancy Act, Sections 88, 188, 53- Raj. Land Revenue Act, Section 125- Order and decree passed by trial court confirmed in appeal by R.A.A. - Held disputed land appears in the Jamabandi of St. 2001-2002 as joint tenancy of plaintiff's father left the village and went to Nayagaon where his mother went in Nata and never returned till filing of suit for cultivating the disputed land or to manage it or to take shares of profits of land- Deletion of plaintiff's father's name during course of settlement operation between St. 2010-2022 never challenged- Deft. remained in continuous open hostile possession of the disputed land till 1994, i.e. St. 2051 when suit filed- The facts admitted during cross- examination in 1995- Long continuous possession upto 40 years of the deft. not controverted- No kind of claim or demand put forward- No documentary evidence after St. 2010 produced in support of averments made in plaint to challenge adverse possession of deft- Sole possession of deft. is an evidence to presume actual custer of the co-tenant of disputed land- Onus of proof was on ptf.- Admission in cross examination by ptf. goes against averment of plaint- Concurrent findings of subordinate courts confirmed, APPEAL DISMISSED" Cases referred: 1. 1996 RRD 280, 2. 1976 RRD 222, 3. 1984 RRD 338, 4. 1988 RRD 337, 5. 1975 RRD 292, 6. AIR 1956 SC 348, 7. AIR 1957 SC 314, 8. 1934P.C. 23, 9. AIR 1964 punj. 187, 10. 1965 ILR 29 Bombay 300, 11. AIR 1959 SC 57,

इस न्याय सिद्धांत में वादी(अपीलांट) पेमा, जेटा, एवं धल्ली जो घूला के वारिस होकर उनके पूर्वज की जमीन पर प्रतिवादी रेषों. नाथू के प्रतिकूल कब्जे



[Signature]
20/11/17
राजस्व अपील प्राधिकारी
श्रीगंगानगर (राज.)

के आधार पर उपखण्ड अधिकारी सागवाड़ा द्वारा खातेदारी अधिकारों की घोषणा की जिसे प्रथम अपील में राजस्व अपील अधिकारी डूंगरपुर द्वारा उपखण्ड अधिकारी का निर्णय बहाल रखा जिसकी द्वितीय अपील माननीय राजस्व मण्डल अजमेर में उपरोक्त अनवानी अपील निर्णय दिनांक 22.01.1989 में विस्तृत व्याख्या कर चादी की अपील खारिज की गई एवं रेषों के कब्जा आधारित खातेदारी अधिकार का निर्णय यथावत रखा जो अपीलांत अभिभाषक द्वारा प्रकरण हाजा में शत-प्रतिशत धरुपा योग्य बताया।

अपीलांत अभिभाषक द्वारा प्रस्तुत न्याय सिद्धांत आर.आर.डी. 2007 पेज 915 अपील नं. 180(5945) अक्टूबर of 2007 माननीय राजस्व मण्डल की डबल बैच का निर्णय दिनांक 01.05.2007 में held किया है। श्री सवाई महाराज जी, श्री तेज सवाई तेजसिंह बनाम फूलचन्द वगैरह में held किया है " Rajasthan Tenancy Act, Section 88, 89- Appeal against order of R.A.A. - Held , appellant is recorded khatedar of the disputed land in Jamabandi Svt. 2045-48 but possession and cultivation is recorded in the name of respondent in Khasra Girdadwari Svt. 2031-36 As per respondent, disputed land was given on patta for cultivation and for grazing animals on 3.5.69 on the basis of yearly lagan of Rs. 10/- Since then, he is in possession - At the time of filing suit, his possession was of 20 Years- Patta issued by his son 'P' on behalf of the appellant, i.e., possession was permissive - According to Ex. 2, 3, 4, 5 lagan was paid for 4 years- Thereafter disputed land was cultivated without permission - Ex. 14, dt. 26.11.75 is admission of appellant in ceiling case which is proof of possession of the respondent - Ex. 17 put up in the court of S.D.O. on 24.9.73 confirms possession of respondent- Reply filed before Collector on 26.11.75 in respect of possession of respondent on Kh. No. 3866 min area 10 bigha is admission- Provisions of Evidence Act say that self-admission is biggest evidence- It is evident that respondent remained in continuous adverse possession of the disputed land for more than 12 years and upto today 30 - Therefore, he is entitled to khatedari rights on the basis of adverse possession. - Order and decree of R.A.A is confirmed- Appeal has no substance. निर्णय के सन्दर्भित पैरा सं. 11- यह स्पष्ट है कि जब स्वयं अपीलार्थी अपने युवराज पुत्र के द्वारा दिये गये पट्टे को अपरोक्ष रूप से अमान्य कर रहे हैं और दूसरी तरफ खुद की तरफ से दिये गये जबाब में विवादित भूमि पर रेषों का कब्जा वास्तु मान रहे हैं तो यह स्पष्ट



[Handwritten Signature]
 20/11/17
 राजस्व अपील अधिकारी
 श्रीगंगानगर (राज.)

है कि उनका यह प्रयास रहा कि रेषों को कब्जे काश्त से बेदखल किया जावे। जब अपीलार्थी को गर्जों के विरोध व प्रयास के विरोध के बावजूद रेषों सं. 1 विवादित भूमि पर 12 वर्ष से बहुत अधिक तक की अवधि तक कब्जे काश्त में है तो निश्चित तौर से यह मामला एडवर्स प्रजेशन का बनता है और विद्वान राजस्व अपील अधिकारी ने रेषों फूलचन्द पुत्र श्री नानकराम शर्मा की अपील स्वीकार करते हुए उसे एडवर्स प्रजेशन के आधार पर उसे खातेदार घोषित करने में कोई गलती नहीं की है।

पैरा सं. 13- अपीलार्थी के विद्वान अधिवक्ता द्वारा अपनी बहस में कथन किया कि पट्टा किसी प्रतापसिंह के द्वारा जारी किया गया है और यह प्रतापसिंह पट्टा जारी करने के लिये अधिकृत व्यक्ति नहीं है। यहां यह विचारणीय है कि जिसे किसी प्रतापसिंह कहा गया है वह व्यक्ति कोई अनजान व्यक्ति नहीं होकर अपीलार्थी महाराजा सवाई तेज सिंह के पुत्र युवराज प्रताप सिंह है तथा विद्वान जिला कलक्टर को 26.11.1975 द्वारा विद्वान उपखण्ड अधिकारी के सामने प्रस्तुत जबाब दिनांक 24.09.1973 के जबाब में स्वीकार किया कि संलग्न सूची के कारतकारों को एक रुपया सालाना प्रति बीघा की दर पर विवादित भूमि काश्त के लिये दी गई है। विद्वान जिला कलक्टर को प्रस्तुत जबाब दिनांक 26.11.1975 में रेषों सं. 1 फूलचन्द का नाम जबाब के पृष्ठ सं. 3 पर स्पष्ट तौर पर अंकित है। इसी प्रकार सीलिंग प्रकरण में विद्वान उपखण्ड अधिकारी (अधिकृत अधिकारी सीलिंग) के यहां प्रस्तुत जबाब दिनांक 24.09.1973 की स्वीकारोक्ति जिसमें रेषों फूलचन्द का कब्जा काश्त माना गया है, को अमान्य घोषित नहीं किया जा सकता। पैरा सं. 14- उपरोक्त विवेचन के प्रकाश में हम इस निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि प्रस्तुत मामले में प्रत्यर्थी प्रतिकूल कब्जे के आधार पर विवादित भूमि के लिये खातेदारी अधिकार प्राप्त करने का अधिकारी है। जैसाकि राजस्व अपील प्राधिकारी ने अपने निर्णय दिनांक 26.08.2000 में निर्धारित किया है। अतएव यह अपील सारहीन होने से खारिज की जाती है एवं राजस्व अपील प्राधिकारी अलवर का निर्णय एवं डिक्री दिनांक 26.08.2000 यथावत रखे जाते हैं।"

अपीलांत अभिभाषक द्वारा उक्त न्याय सिद्धांत के आधार पर राज.काश्त. अधि. की धारा 88 में प्रतिकूल कब्जा के आधार पर घोषणात्मक दावा विवेचित होकर प्रकरण हाजा पर चरपा योग्य होकर अनुलोप का निवेदन किया।

[Signature]
 20/11/17
 राजस्व अपील प्राधिकारी
 श्रीवांगनगर (राज.)



अपीलांट अभिभाषक द्वारा प्रस्तुत न्याय सिद्धांत आर.आर.डी. 2009 पेज 252 अपील ID No 385,386 करौली of 09 धनसिंह बनाम गिलासी वगैरह . माननीय राजस्व मण्डल अजमेर की डबल बेंच का निर्णय दिनांक 21.01.2009 में held किया है कि " Rajasthan tenancy Act, Section 88, 188, 53- Appeal against order of R.A.A - Held disputed land is in joint khatedari of parties- Dispute is regarding Kh. No. 663 & 238- Trial court has discussed verbal evidence and documents in detail in para 3 of the order- Khatekdar is grand father of plaintiff No. 1 and father of plaintiff No. 2 - Kh. No. 663 was in possession of ' M' by caste Mail according to certified copy Ex.2 of the uyardari of Settlement deptt.- ' M' fatere of defl. No.2 has written on an ordinary paper dt. 15-11-59 in favour of 'S' Ex.3 that expenditure of suit done by him and thus plaintiffs are sole khatedars of Kh. No. 663 - Ex. 3 is unregd. and 30 Years old- as per principles of law 30 yrs. old document will be deemed true- Document Ex-2 is forged has not been certified by any court- Apart from it, possession of ptff. in uyardari is proved as per order of Settlement Officer (Ex.2) dt. 26.7.60 which confirmed the document dt. 15.11.59- Issue No.2 decided on the basis of evidence- Kh. No. 238 has been kept by trial court in the share of ' K' and 'J' as 1/3 share each - 'J' transterred his 1/3 share to ' S' by regd. sale- After transfer share of 'S' comes to 2/3 in Kh. No. 238 - Defondant, thus, is not entitled to declaration - No interference is required in the concurrent findings of subordinate courts- Orders of Asst. Collector and R.A.A. confirmed. "

अपीलांट के अभिभाषक का कथन है कि यह प्रतिकूल कब्जे को साबित करने के लिए दस्तावेज की guinness के परीक्षण से सम्बन्धित है जो अर्धी. न्यायालय द्वारा तनकी सं. 1 का निर्णय विधिसम्मत किया है। इस न्याय सिद्धांत से उसका endorsement साबित होकर अपीलांट खातेदारी अधिकार घोषणा का अधिकारी है।

विद्वान अभिभाषक रेषों द्वारा जाहिर किया कि अपीलांट अभिभाषक द्वारा प्रस्तुत न्याय सिद्धांत पुरानी होकर इसके विपरीत नवीनतम कई निर्णय होकर अपीलांट के न्याय सिद्धांत over-rule हो चुके हैं तथा अपनी लिखित बहस में जाहिर किया कि " क्या राज.कास्त.अधि. की धारा 88 के अन्तर्गत प्रतिकूल कब्जे के आधार पर खातेदारी अधिकार दिये जाने का कोई प्रावधान अधिनियम में है तथा हस्तागत प्रकरण में प्रतिकूल कब्जा का तथ्य प्रमावी होता है अथवा नहीं" के

20/11/12
 राजस्व अपील प्राधिकारी
 श्रीगंगानगर (राज.)



प्रत्युत्तर में कि प्रतिकूल कब्जे के आधार पर खातेदारी अधिकार नहीं दिये जा सकते से सम्बन्धित न्याय सिद्धान्त पेश किये। आर.आर.डी. 2011 पेज 508 जगदीश वगैरह बनाम सीताराम वगैरह Reference No. 2964/Jaipur of 97 माननीय राजस्व मण्डल अजमेर की Full bench में held किया है कि निर्णय के सन्दर्भ पैरा सं. 38 से 79 का पठन है कि "38. A careful reading of the judgment passed by the Larger Bench cited 1991 RRD Page 1 gives clear picture that it has been passed on the basis of following propositions:—

1. The general law of limitation is applicable to proceedings under the Tenancy Law. Application of Section 27 of the Limitation Act is not excluded.

2. By adverse possession, the trespasser acquires khatedari rights under the Rajasthan Tenancy Act, 1955.

39. In this regard, we have to be very prudent in examining these propositions in the light of arguments advanced, provisions of relevant laws and judicial pronouncements.


40. It is a fact that the State Legislature has enacted the Rajasthan Tenancy Act and Rajasthan Land Revenue Act for regulating tenancies of agriculture holdings in the State. Both these Laws are special laws, wherein the provisions pertaining to terms and conditions of the tenancies, maintenance of Revenue records, survey and settlements, transfer of tenancies, inheritance, creation of courts, resolution of disputes etc. have been provided. The Acts are comprehensive in nature and coverage.

41. It is also settled proposition that the provisions of the State Special statute will prevail over provisions contained in general law. The Hon'ble Apex Court has held in AIR-1963 (SC) 1077 that :-

"a general act must yield to a special act dealing with a specific subject matter and that if an Act directs a thing to be done in a particular way, it shall be deemed to have prohibited the doing of that thing in any other way....."

This view has been consistently upheld in judicial pronouncements e.g. reported in AIR 1931 (PC) Page 149, AIR 1961 (SC) 117, and SCC 1998 (7) Page 162.

42. It is also noted that Rajasthan Tenancy Act, a special Act was brought about with the object of providing certain measures of land reforms and its provision has overriding effect, though they may not always be consistent with the provisions of general law. Having made the general law if the legislature subsequently makes a special Act and provides for special provisions, it can be safely assumed that the legislature had in mind the provisions prevailing in general laws but chose to make a special law with a specific objective and lay down provisions which are different or in exception to the general law.


20/11/12

राजस्व अपील प्राधिकारी
भोपाळ (राज.)

43. It is also well settled principle in law that the court cannot read anything into a statutory provision which is plain and unambiguous. The language implied in a statute is determinative factor of the legislative intent. If the language of the enactment is clear and unambiguous, it would not be proper for the courts to add any words thereto and evolve some legislative intent not bound in the statute.

Hon'ble Supreme court In 2001 (9) SCC Page 673 P. Nirathlingam Vs. Annayu Hadar and ors. has observed that

"Interpretation which defeats the very intent and purpose for which a statute was enacted should be avoided even if such interpretation has long been accepted and followed."

Herein also on the basis of long possession, no ground has been incorporated in Rajasthan Tenancy Act, 1955 on which khatedari rights can be given on the basis of adverse possession having foundation of long cultivatory possession.

44. In this context the Rajasthan Tenancy Act, which is a special law has its own provisions for limitation in various matters. Such provisions are enumerated in Third Schedule of the Act which provides for period of limitation in various matters which are somewhat different from the provisions of Indian Limitation Act. In addition the Act has also provided Section 214 wherein the extent of applicability of the Indian Limitation Act has been given. Section 214 of the Act reads as under :

- (1) The suits and applications specified in the Third Schedule shall be instituted and made within the time prescribed therein for them and every such suit instituted or application made after the expiry of the period of limitation so prescribed shall be dismissed:

Provided that any such suit or application, for which the period prescribed by the said Schedule is shorter than the period prescribed by the law in force before the commencement of this Act, may be instituted or made within six months next after the commencement of this Act or within the period of limitation prescribed by the aforesaid law, whichever period expires first :

Provided further that any such suit or application for which a period of limitation is prescribed by the said Schedule but for which no period is prescribed by the aforesaid law may be instituted or made within the period prescribed by the said Schedule computed from the date of the commencement of this Act.

- (2) If the payment of rent has been suspended under the order of a competent authority on account of an agricultural calamity, the period of suspension shall be excluded in the computation of the period of limitation prescribed for a suit for the recovery of such rent.

- (3) Subject to the provisions contained in sub-section (1) and (2) the provisions of the Indian Limitation Act, 1908 (Central Act IX of 1908) shall apply to suits, appeals, applications and proceedings under or in pursuance of this Act.

45. The scope of Section 214 of the Rajasthan Tenancy Act, 1955 makes it explicitly clear that this provision has been introduced with a view to regulate the period of limitation prescribed in the Third Schedule. It has been made applicable to



20/11/17
राजस्व अपील प्राधिकारी
भोपालनगर (राज.)

suits, applications and proceedings under Rajasthan Tenancy Act and this section has been enacted to serve this purpose. This is also settled law that law of limitation is a rule of procedure and does not create any substantive rights in favour of any person nor do they define or create causes of action, but simply prescribe that the remedy can be exercised only upto a certain period and not subsequently. Full Bench of the Madhya Pradesh High Court In AIR 2001 M.P. Page 268 also held that: —

"where special period of limitation is prescribed under the special act, the same shall prevail over the limitation prescribed under the Limitation Act, 1963."

46. Section 214(1) of the Act says that the suits and applications specified in the Third Schedule shall be instituted and made within the time prescribed therein for them. It is also evidently clear that as per Section 214(3) of the Act provisions of Indian Limitation Act are applicable to the Act subject to the Third Schedule, meaning that Limitation Act shall apply for deciding the limitation in cases for which no time limit is specified in the Third Schedule for filing suits, appeals, applications and proceedings under or in pursuance of this Act. This section only speaks about the time limit for instituting suits etc and not for conferment of khatedari rights on adverse possession. As discussed earlier, conferment of khatedari right to a trespasser on the basis of adverse possession are not envisaged in any of the sections of the Act, being a special law for agricultural tenancies, which are clearly not lull proprietary rights.

47. As per observations of the Full Bench of the Madhya Pradesh High Court reported in AIR 2001 (M.P.) page 268 while relying on apex Court decision in the case of 'Mathura Lal Vs. Keshar Bal' cited in AIR 1971 Supreme Court Page 310, it has been held that: —

"In the case governing the special acts dealing with specified rights created or recognized subject to Limitation Act. Restrictions in the absence of any provision, no such contingency could arise as special always excludes the general. There could be no mixing up of the two."

48. In the case of 'Tulsi Ram Jivan Lal Lodi Vs. Ryder Lana Pinjam' reported in AIR 1944 Nagpur Page 250 rendered by a full bench, it has been observed that: —

"The legislature when applying Section 28, Limitation Act, 1908 (Section 27 of the Limitation Act, 1963), to suits between tenant and trespasser which provision extinguishes the tenant's right after exclusion for the prescribed period did not confer by implication tenancy right on the trespasser against the landlord."

49. It was repeatedly argued during the hearing that the provisions of Indian Limitation Act, specially Article 64 and 65 will apply to the Rajasthan Tenancy Act. In this context, it is necessary to point out that the Indian Limitation Act is mainly a procedural law though under Article 64 and 65, rights can be claimed by individuals on the basis of possession and title. We are of the view that as Article 64 and 65 of the Indian Limitation Act are substantive in terms of providing rights to an individual on the basis of title and possession; they cannot be taken to be applicable to the Rajasthan Tenancy Act merely with reference to Section 214(3) of the Rajasthan Tenancy Act. While we do find provisions in Rajasthan Tenancy Act i.e. Section 63(1)(iv) which corresponds to Section 27 of the Indian Limitation Act, we



20/11/17
राजस्व अपील प्राधिकारी
भोपाळ (रज)

do not find any clear cut para materia reference of Article 64 and 65 of the Indian Limitation Act in the provisions of Rajasthan Tenancy Act. Hence the argument that Article 64 and 65 become applicable in Rajasthan Tenancy Act through the door of a very procedural Section 214(3) would be drawing a very far fetched interpretation and building substantive rights, where none exists. In this context, it is also relevant to dwell upon the intention of the legislature it would appear that the State legislature has deliberately chosen not to make similar provision for Article 64 and 65 of the Indian Limitation Act in the special statute of the State though Article 27 have found a corresponding place in Section 63(1)(iv) of the Act.

50. On the basis of above analysis, we cannot infer that Article 64 and 65 will ipso facto become the part of the provisions of the Rajasthan Tenancy Act and thereby confer rights and opportunities not specifically mentioned anywhere in the Act. Hence, the provisions of law of limitation have limited application in the matters pertaining to the tenancy law in the State and further the extinguishment of the right under Article 27 of the Limitation Act will not automatically result in the accrual of tenancy rights.

51. Now coming to the second proposition laid by the larger bench in 1991 RRD Page 1 that by adverse possession the trespasser acquires khatedari rights.


52. It is clear from the preamble and the provisions of the Rajasthan Tenancy Act that it is a measure of land reforms intended to provide khatedari rights on agriculture land with a view to ameliorate the conditions of the farmers and cultivators. Under the special Act, sections notably 12(2), 13, 15, 19, 189(2), 193 and 194(2) provide for conferment and accrual of khatedari rights meaning thereby providing wide and en masse coverage and opportunities.

53. Section 7 of the Rajasthan Tenancy Act, 1955 provides that State is the land owner in respect of the land held by tenant directly from the State Government. After resumption of jagirs and abolition of biswedari system, the revenue land now fiery vests in the State Govt. who is the landholder having the proprietary right. Hence, no one else is allowed to have the proprietary right over agricultural land. In simple words, State is the owner of all revenue lands and for the purpose of land reforms, provisions have been made for conferment of the khatedari rights to the tenants and sub-tenants.

54. Viewing from another angle, definition of tenant as narrated in Section 5 sub-clause 43 is as under: -

"5(43) 'Tenant' shall mean the person by whom rent is, or, but for a contract, express or implied, would be, payable and, except when the contrary intention appears, shall include —

- (a) In the Abu area, a permanent tenant or a protected tenant,
- (b) In the Ajmer area, an ex-proprietary tenant or an occupancy tenant or a hereditary tenant or a non-occupancy tenant or a Bhooswami or a Kashtkar,
- (c) In the Sunel area, an ex-proprietary tenant or a pakka tenant or an ordinary tenant,
- (d) a co-tenant,
- (e) a grove-holder,


20/11/17
राजस्थान अपील प्राधिकारी
बीरगान्धर (राज.)



- (f) a village servant,
- (g) a tenant holding from a land owner
- (h) a mortgagee of tenancy rights, and
- (i) a sub-tenant.


but shall not include a grantee at a favourable rate of rent or an ijaredar or thekadar or a trespasser."

55. This definition is exhaustive and specifically exclude the trespasser within the ambit of the tenant. A khatedar tenant is one of the tenants mentioned in Section 14 of the Rajasthan Tenancy Act, 1955. Such a tenant has a right to bequeath his interest under Section 39 of the Tenancy Act and can transfer his interest under Section 41 of the same Act on conditions specified in Section 42 and 43. His interest is heritable under Section 40 as well, but it is not sufficient in law to make him the owner of the property. A khatedar tenant admittedly is a person by whom rent is payable. The effect of it in law is that such a person cannot be deemed to be an absolute or unlimited owner which is necessary before the right of the adverse possession can be exercised.

56. As we have a special statute to regulate and administer various aspects of tenancies in the State we shall have to refer to the specific provisions provided in this Act. As we have already discussed that rights of a tenant in agricultural tenancies are heritable and transferable yet they do not constitute ownership and hence they are not proprietary rights (1994 SCC (5) 5621. It has also been considered earlier that the existing provisions in Rajasthan Tenancy Act do not allow conferment of tenancy rights on the basis of adverse possession and there is no para materia of Article 64 and 65 of the Indian Limitation Act.

57. The M.P. High Court in its full bench decision cited in AIR 2001 MP 268 unequivocally inferred that no mode other than the modes prescribed for conferment, acquisition or accrual of Bhumiswami rights in the special statute can be created or presumed to exist so as to entitle even a trespasser to become a tenant by adverse possession. The existing definition of a tenant given in Section 5(43) of the Act explicitly prohibits a trespasser to be a tenant. More importantly the land owner in the State is the State Government therefore any adverse possession against the tenant cannot be considered against the true owner. We are in agreement with the arguments advanced by learned advocate for the appellants that in matters of agricultural tenancies in the State the basic condition of acquiring title on the basis of adverse possession can never be fulfilled because the land holder/owner is the State. We are fortified by the citations mentioned in 2007 (1) RRT SC 311 in this regard. In these circumstances we are of the opinion that in agricultural tenancies the law of adverse possession does not apply in our State.

58. It is also settled position that when special act is silent on a particular subject, then apart from the general law, intention of the legislature for enactment of the special law is paramount and due consideration must be given to the aims and objects for which special statute has been promulgated. In the light of above scenario, applying the same principle in the case in hand, here the intention of the legislature is clear as to not to give the trespasser a status of the tenant by virtue of the exclusion clause contained under Section 5(43) of the Rajasthan Tenancy Act, 1955. 59. The observations arrived in para 15 to 17 of the judgment in question - RRD 1991 page 1 also make it clear that the learned larger bench was impliedly of


20/11/17
राजस्व अपील अधिकारी
श्रीमंगलम् (राज.)

the view that the possession of a trespasser during the continuance of a lease does not become adverse against the lessor who is in possession by receipt of rent from his lessee. It has also been observed that in revenue cases, State continues to be the owner of the land as lessor and the tenant in the capacity of lessee. Therefore, a suit for declaration by trespasser on the ground that he has acquired khatadari rights by adverse possession will not bind the State.

60. In view of the facts and circumstances narrated above, there can be no escape from the conclusion that no mode other than the modes prescribed for conferment, acquisition or accrual of tenancy rights can be created or presumed to exist or assumed as to entitle a trespasser having inferior rights to become a land owner or a tenant by adverse possession. The ratio of the decision of the apex Court in the case of 'Deendayal and another Vs. Rajaram' (AIR 1970 Supreme Court Page 1019) can be safely applied to the legislative scheme underlying the provisions of the Rajasthan Tenancy Act, 1955 which says :

"It is one thing to say that a tenant who was in possession of the tenancy holding at the time of his possession had lost his rights in the holding but it is another thing to say that a trespasser had become the tenant of that holding at the end of the prescribed period."

61. The Rajasthan Tenancy Act, 1955 is exhaustive and the principles available in general law that the extinguishment of the title of the rightful owner will operate as good title of the wrong doer or extinguished in favour of a true owner is wholly alien to the scheme of the above Act.

62. The ratio of the full bench case cited in A.I.R. 1923 Privy Council page 118 has given edifice to the legal structure that:-

"Limitation Act, S. 28 - Mere lapse of time does not transfer right in property. — A right of property which is vested in one person is not transferred by the mere lapse of time to the person actually in possession."

63. The Full Bench of the Nagpur High Court in 'Putija Ram Vs. Ramu Chintoo' reported in AIR 1940 Nagpur Page 49(F.B.) has also observed that a tenancy cannot be acquired by adverse possession. Bare perusal of the judgment cited in 1991 RRD Page 1 clearly shows that it was passed on the principles enunciated in AIR 1980 M.P. Page 183. It will be in the interest of justice to mention that judgment cited in AIR 1980 M.P. Page 183 has been overruled by the Full Bench of the same High Court in the case of 'State of Madhya Pradesh Vs. Balveer Singh' cited in AIR 2001 M.P. Page 268 (F.B.).

64. The larger bench of this court erred in holding that though tenancy law is a special enactment but it is also part of the general law of the land. This bench does not conform to the views expressed by the larger bench in this respect, Rajasthan Tenancy Act is a special statute and it outweighs the general law as far as the tenancy matters are concerned. The full bench decision of M.P. High Court cited in AIR 2001 M.P. 268 removes all confusions in this regard: —

"In view of the facts and circumstances noticed hereinabove, there can be no escape from the conclusion, that no mode other than the modes prescribed for conferment, acquisition or accrual of Bhumiswami rights can be created or presumed to exist or assumed so as to entitle a cultivator or tiller of the soil or even a trespasser having



20/11/17
राजस्थान अधीन प्रधिकारी
श्रीगंगाधर (राज)

inferior rights to become a Bhumiswami envisaged under Section 157 of the Code or a tenant as envisaged under the Code by prescription or by adverse possession. The ratio of the decision of the Apex Court in the case of Dindayal Vs. Rajaram (AIR 1970 SC 1019) (supra) can be safely applied to the legislative scheme underlying the provisions of the Code and nature of the rights with reference to the soil or land as envisaged under the Madhya Pradesh Land Revenue Code, 1959."

65. It is also evident that the larger bench of this court did not consider this vital issue that there is no provision to confer tenancy rights in the special statute and the applicability of Indian Limitation Act provisions have also been restricted by the legislature in Section 214 of the Act. When the legislature did not intend to provide for the tenancy rights to the adverse possessor how can the courts grant it and under what provisions? The larger bench though did accept the principle of the law that the tenant has no title to the land and he is merely a lessee. In such a situation when the tenancy rights are not ownership rights, how can the law of adverse possession operates against the tenant who is not a true owner.


66. In our humble opinion the view taken by the larger bench of this court is erroneous and does not stand to the legal scrutiny, it has some innate contradictions of law points which create more confusion than clarity.

67. So as per the discussion given above, two propositions created by the learned Larger Bench in 1991 RRD Page 1 have not considered the important legal points as enumerated above. So in the eyes of the law, the concept created by learned larger bench in 1991 RRD Page 1 has become no longer a good law.

68. Much reliance has been placed by the learned counsel for respondent and learned amicus curiae(s) on the judgments pronounced in citations 'Shri Khuman Mal Vs. Shri Rheru' RBJ 1994(1) Page 50 and 'Smt. Anup Kanwar and Ors. Vs. Smt. Prem Kanwar and ors.' 2008 RRT (2) Page 799. In these cases it has been argued by the learned counsel for respondents and amicus curiae(s) that the Hon'ble High Court has explicitly ruled that an adverse possessor can bring a suit under Section 88 of the Rajasthan Tenancy Act for declaration of his tenancy rights unless such rights are prohibited by law.

69. We have respectfully gone through these judgments. One of the cases was related to agricultural tenancy belonging to a member of scheduled caste. The Hon'ble High Court in this case has held that it is well settled proposition of law that State is the owner of land and khatedari rights can be granted only under the provisions of Rajasthan Tenancy Act but one has to justify that his possession over the land is in accordance with law.

70. It seems, that the issue of limitation for claiming the rights on the basis of adverse possession has not been given in the statute nor is there any provision in Rajasthan Tenancy Act to confer khatedari rights to an adverse possessor, was not specifically agitated before the Hon'ble High Court. Perhaps this was also not brought to the notice of the Hon'ble High Court that when the true owner of the land is the State how can the adverse possession against a tenant, be construed as adverse possession against the true owner. It further appears that, this issue was also not raised and adjudicated before the Hon'ble bench that Rajasthan Tenancy Act is a special law enacted as a measure of land reform wherein there is no provision to confer khatedari rights merely on the basis of adverse possession or there is no


20/1/17
राजस्व अपील प्राधिकारी
श्रीरंगनाथ (राज.)

equivalent provision of Article 64 and 65 of the Indian Limitation Act in the Rajasthan Tenancy Act.

In such circumstances the intention of the legislature is to be seen that whether the legislature deliberately chose not to provide for such conferment of rights. The Hon'ble High Court in its above quoted judgment [1994 (1) RBJ Page 50] has held:—

"-----more so, Section 88 of the Act under which the present suit has been Med clearly envisages that by adverse possession the trespasser acquires khatedari rights provided that the acquisition of khatedari is not specifically prohibited by law, which means that if a person claiming to have acquired khatedari rights by adverse possession was put in or had obtained possession of the land in contravention of any provisions of law prohibiting or invalidating the transaction which has occasioned such adverse possession or if any such provision of any State was thereby circumvented will not be entitled to acquire khatedari rights unless he shows that right by way of adverse possession is justified and not otherwise prohibited in law."

71. With all humility this bench feels that the real issue pertaining to conferment of khatedari rights entirely on the basis of adverse possession in the background of the provisions mentioned in the special statute was not at all raised and adjudicated before the Hon'ble High Court. Hon'ble Apex Court in judgment cited at (1994) 5 SCC Page 562 has held that : —

"tenancy rights are not proprietary rights, therefore, law of adverse possession does not apply to the agricultural holdings in the State."


More so because Tenancy Act is a special Act legislated as a measure of land reforms and it does not provide such conferment, it is also very pertinent to refer here the words used in the preamble of Rajasthan Tenancy Act.

"An Act to consolidate and amend the law relating to tenancies of agricultural lands, and to provide for certain measures of land reforms and matters connected therewith."

72. In this way if tenancy rights are conferred on the basis of adverse possession by the courts when there is no provision in this special Act it will be against the basic structure and scheme of the statute. The Act was legislated to provide permanent relief to the peasantry. This Act, as measure of land reform was put in the ninth schedule of the Constitution as a safeguard measure. In such a case if adverse possession is made a basis of conferment of khatedari rights it will be a retrograde step to land reforms.

73. In these circumstances, this bench is of the opinion that intricate issues involved in this concept with regard to the provisions of conferment of khatedari rights to an adverse possessor were not raised and adjudicated before the Hon'ble High Court. In these cases issue of conferment of khatedari rights on the basis of Article 64 and 65 of the Indian Limitation Act and allied grounds were not in focus before the Hon'ble High Court. Therefore, the above citations do not apply substantially on the case in hand.

74. However even if for the sake of arguments, we assume that the law of adverse possession is applicable to the provisions of the Rajasthan Tenancy Act, 1955 and a


20/11/17
राजस्व अपील प्राधिकारी
क्षेत्राधिकार (राज.)



khatedari right can be given under said Act on the ground of adverse possession, then too we need to look at the view cited in apex Court's judgment in the case of Hemaji Vaghaji Jat Vs. Ishikhabhai Khengarbhai Harijan reported in AIR 2009 Supreme Court Page 103 wherein it has been held:-

"law of adverse possession which ousts an owner on the basis of inaction within limitation is irrational, illogical and wholly disproportionate. The law as it exists is extremely harsh for the true owner and a windfall for a dishonest person who had illegally taken possession of the property of the true owner.

The land ought not to benefit a person who in a clandestine manner takes possession of the property of the owner in contravention of law. This in substance would mean that the law gives seal of approval to the illegal action or activities of a rank trespasser or who had wrongly taken possession of the property of the true owner."

75. In the light of the above discussions, arguments advanced by the learned counsels, supporting the conclusion of the judgment cited in 1991 RRD Page 1 and other rulings cited by them do not support them in the peculiar and distinguishable facts of the present case.

76. Further, it is undisputed and accepted by all the learned counsels arguing in this case, that the Board of Revenue has no legislative power to lay down a new law. Hon'ble Supreme Court in the case of 'Saathi Devi Vs. Prasanna and ors., cited in AIR 2010 Supreme Court Page 2777 (supra) has held that courts have no power to legislate.

77. In view of what has been discussed above and the legal precedence, this bench answers the questions raised by the referring D.B. in the following manner:—

(1) Whether the Larger Bench in its judgment 'Bagga Vs. Surendra Singh' as reported in 1991 RRD Page 1 has laid down a good law by providing for conferment/acquisition of khatedari right on a trespasser on the basis of 'adverse possession' vis-a-vis the provision of the Rajasthan Tenancy Act of 1955 as a measure of land reform?


Answer:— In the view of this bench the Larger Bench in its judgment 'Bagga Vs. Surendra Singh' as reported in 1991 RRD Page 1 has not laid down a good law because the Rajasthan Tenancy Act does not have any provision to confer tenancy rights to the adverse possessor. This bench also infers that providing tenancy rights to the adverse possessor is a retreating step with regard to land reforms and such a conferment of tenancy rights is against the basic spirit of this special legislation.

(2) Whether extinguishment of tenancy right under Section 63(1)(iv) of the Act of 1955 creates khatedari right in trespasser on the basis of adverse possession?

Answer:- In the opinion of this bench extinguishment of tenancy rights create no khatedari rights in the trespasser on the basis of adverse possession.

(3) Whether the Board of Revenue has legislative power to lay down a new law for grant of khatedari right in addition to and over and above what is provided under the Act, as has been done by the Larger Bench of this Court in 1991 RRD Page 1?

Answer :— In the opinion of this bench the Board of Revenue does not have legislative power to lay down a new law for grant of khatedari rights.


20/11/17
राजस्व अपील प्राधिकारी
श्रीगंगानगर (राज.)

(4) Whether the judgment of the Larger Bench as reported in 1991 RRD Page-1 should be revoked/annulled in light of the provision of the Act of 1955 and 1 the judgment of the Hon'ble Supreme Court of India as reported in RLW 2008 (1) RJ-Page 1101.

Answer :— In the opinion of this bench the judgment of larger bench in Bagga Vs. Surendra Singh as reported In 1991 RRD Page 1 being not a good law, deserves to be set aside.

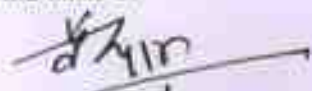
78. Before parting with the case we would like to convey our gratitude to all the participating members of the bar who have assisted us in rendering this judgment.

79. Since we have answered the questions referred to us, the matter may now be placed before the concerned bench for decision of the appeal in accordance with law.

Pronounced in open court."

जो प्रकरण हाजा पर चस्पा योग्य होकर प्रतिकूल कब्जे के आधार खातेदारी अधिकार नहीं दिये जा सकते जाहिर किया। रेस्पों अभिभाषक द्वारा प्रस्तुत दूसरा न्याय सिद्धांत आर.बी.जे. 2016 पेज 340 चैनाराम व अन्य राजस्व मण्डल अजमेर SB Civil Petition No. 13043 of 2015 में held किया है कि " Rajasthan Tenancy Act, 1955 - Section 88- Khatadari rights can not be conferred on the basis of adverse possession. It is also observed that in 2011 RRD 508 the Full Bench of the Board of Revenue held that no khatadari right can be awarded on the basis of adverse possession. The said proposition has further been reiterated by the Hon'ble Larger Bench of the Rajasthan High Court vide judgment dated 15-07-2015, in the case of Tara Vs. State of Rajasthan. After perusing the finding given by the learned Board of Revenue and upon the fact that land in question was purchased by Respondent No. 4 by registered sale- deed dated 5.4.1962 and on same day possession was taken by the defendant, no error has been committed by the learned Board of Revenue to set aside the judgement of the learned Revenue Appellate Authority-cum-Settlement Officer dated 19-07-2001. Therefore, the instant Writ Petition is hereby dismissed. Writ petition dismissed."

निर्णय के सन्दर्भ में पैरा सं. 6 व 7 का text है कि " 6. The learned Counsel for the petitioners submits that Revenue Appellate Authority allowed the Appeal filed by the appellants on the ground of adverse possession, but the learned Board of Revenue quashed and sit aside the finding of adverse possession and held that Revenue Appellate Authority has committed an grave error white allowing the Appeal on the ground of adverse possession in view of the judgement reported in 1981 RRD 549 and reported in 1985 RRD 648 in which it has been held that once permissive possession has been pleaded then no decree can be passed on the basis of


20/4/17
राजस्व अपील प्राधिकारी
भौगोलिक (राज.)



adverse possession. It is also observed that in 2011 RRD 508 the Full Bench of the Board of Revenue held that no Khatedari rights can be awarded on the basis of adverse possession. The said proposition has further been reiterated by the Hon'ble Larger Bench of the Rajasthan High Court vide judgement dated 15.7.2015, in the case of Tara Vs. State of Rajasthan.

7. After perusing the finding given by the learned Board of Revenue and upon the fact that land in question was purchased by Respondent No. 4 by registered sale-deed dated 5.4.1962 and on same day possession was taken by the defendant no error has been committed by the learned Revenue Appellate Authority-cum-Settlement Officer dated 19.7.2001. Therefore, the instant Writ Petition is hereby dismissed."


रेस्पों. अभिभाषक द्वारा प्रस्तुत अन्य न्याय सिद्धांत आर.बी.जे. 2015 पेज 648 मोहनलाल सुखाड़िया विश्वविद्यालय बनाम चैनाराम में राजस्व मण्डल डबल बैंच का निर्णय अपील डिक्री/टी.ए./4896/2001 उदयपुर के निर्णय में held किया है कि " Appeal Decree/TA/ 4896/2001/ Udaipur,

Mohan Lal Sukhadia University Udaipur through Shri Mohan Lal Sharma, Registrar, Mohan Lal Sukhadia University, Udaipur Tehsil Girva Distt. Udaipur — Appellant

Versus

Chenaram son of Onkar Lal Dangi resident of Nokha Tehsil Girva Distt. Udaipur & Ors. — Respondents

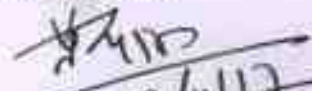
D.B. Shri Sanjay Kumar, Member, Shri Vijay Kumar Soni, Member
Rajasthan-Tenancy Act , 1955- Section 88- Khatedari rights cannot be acquired on agricultural land on the basis of adverse possession. In toto the trial court (Assistant Collector) (Headquarters) Udaipur rightly came to the conclusion after an issuewise judgment that the present respondents (plaintiffs) had failed to prove their case. The learned Settlement Officer-cum-Revenue Appellate Authority, Udaipur on the specious ground of adverse possession has reversed the judgement of the trial court which as mentioned is contrary to law and facts and also contrary to the ratio in ruling of the Full Bench of his Hon'ble Court and susequent judgment. Therefore , in view of the discussion, this present second appeal deserves to allowed. Appeal allowed." निर्णय के संदर्भ पैरा 5 की इबारत है कि " 5. As per 1981 RRD 549 and 1995 RRD 648, it is clear that once permissi-ble possession has been pleaded then no decree can be passed on the basis of adverse possession. In 2011 RRD 508, the ratio by the Full Bench of the Honble Board of Revenue has succinctly held that


20/11/17
राजस्व अपील प्राधिकारी
झोंगरानगर (राज.)



no khatedari rights can be awarded on the basis of adverse possession. This position has further been reiterated recently by the Hon'ble Larger Bench of the Rajasthan High Court vide judgment dated 15.7.2015 given in Tara Vs. State of Rajasthan and other connected case wherein it has also been held that adverse possession confers no khatedari rights on a person. If we study the impugned judgment passed by the learned Settlement Officer-cum-Revenue Appellate Authority, Udaipur it is absolutely clear that while reversing the judgment of the trial court, the learned Settlement Officer-cum-Revenue-Appel-late Authority, Udaipur has come to the conclusion that the present respondents have acquired adverse possession on the land concerned, therefore, khatedari rights have been given to the present respondents. It is absolutely clear from the plaint, issues framed that adverse possession was never the contention of the present respondents before the trial court. their case was based on permissive possession. Therefore, the learned Settlement Officer-cum-Revenue Appellate Authority, Udaipur has come to the absolutely wrong conclusion that on the basis of adverse posses-sion khatedari rights be given to the respondents. Also, the view taken by the learned Settlement Officer-cum-Revenue Appellate Authority, Udaipur is contrary to the ratio of the Full Bench judgment of this court passed in 2011 RRD 508 which has been reiterated in the recent Larger Bench judgment of Tara Vs. State of Rajasthan and other appeals passed by Honible Rajasthan High Court. It is also clear that as per Section 92 of the Indian Evidence Act once the document has been ad-mitted and proved before a competent court, then no oral evidence can be taken against such document. The sale deed which was effected in favour of the present appellants in view of Section 92 of the Indian Evidence Act does not suffer from any infirmity. The case of the present respondents before the trial court was based on a patta which was never produced before the trial court. If we read Exhibit-6 carefully we find no evidence that possession of the disputed land was handed over to the present respondents. The case of the present respondents before the trial court was based on their acquiring a patta of the land in question which however was never produced before the trial court. The contention of the learned counsel for the respondents was also that in view of the fact that the considera-tion of the patta was below Rs. 100/-, therefore, no registration of the panel was applicable in the present case. We find that the concerned patta through which the plaintiffs claim their right was not even produced before the trial court. Ex-hibit-6 no where mentions that the possession of the said land was handed over to the respondents. In toto the trial court (Assistant Collector)





20/11/17
राजस्व अपील अधिकारी
श्रीवांगनगर (राज.)

(Headquarters) Udaipur rightly came to the conclusion after an issuewise judgment that the present respondents (plaintiffs) had failed to prove their case. The learned Settlement Officer-cum-Revenue Appellate Authority, Udaipur on the specious ground of adverse possession has reversed the judgment of the trial court which as mentioned above is contrary to law and facts and also contrary to the ratio in ruling of the Full Bench of this Hon'ble Court and subsequent judgment. Therefore, in view of the discussion above, this present second appeal deserves to be allowed. Following orders are passed. This appeal under Section 224 of the Act is hereby allowed. The impugned judgment/decreed passed by the learned Settlement Officer-cum-Revenue Appellate Authority, Udaipur dated 19.7.2001 is hereby quashed. The judgment/decreed passed by Assistant Collector (Headquarters) Udaipur dated 21.11.2000 is upheld. The record be sent forthwith.

Pronounced."

रेसॉ. अभिभाषक द्वारा प्रस्तुत न्याय सिद्धांत आर.आर.टी. 2012 पेज 904 में माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा स्टेट आफ हरियाणा बनाम मुकेश कुमार एवं अन्य Petition for special leave to Appeal(C) NO. 28034 of 2011(Arising out of CC 9038 of 2010) निर्णय दिनांक 30.09.2011 में held किया है कि - " Limitation Act, 1963 - Articles 64 & 65 - Suit for declaration on the ground of adverse possession - Police department was trying to grab the land of the defendant - suit dismissed- counter claim of defendants decreed -Govt. should protect the property of a citizen- Property recorded in the name of defendants in the revenue records- Concurrent findings- Right to property is not only a constitutional or statutory right but also a human right - law of adverse possession is required to be looked afresh- Held, SLP is liable to be dismissed with cost of RS. 50000/- ."


अभिभाषक अपीलेंट द्वारा रेसॉ. अभिभाषक द्वारा प्रस्तुत न्याय सिद्धांतों का प्रतिकार कर बताया कि रेसॉ. अभिभाषक द्वारा जो भी न्याय सिद्धांत पेश किये हैं उनकी विषयवस्तु, पृष्ठ भूमि merits प्रकरण हाजा के तथ्यों से पूर्ण रूपेण भिन्न होने तथा इन न्याय सिद्धांतों में अपीलेंट द्वारा प्रस्तुत न्याय सिद्धांतों को discuss नहीं किया है और न ही किसी रूप में discredit किया है। अतः रेसॉ. द्वारा प्रस्तुत ये न्याय सिद्धांत प्रकरण हाजा पर चर्चा नहीं होते हैं तथा अपीलेंट द्वारा प्रस्तुत न्याय सिद्धांत आज भी प्रभावी होकर प्रकरण हाजा पर चर्चा योग्य हैं। अतः अपील अपीलेंट अपील में घोषणात्मक दावे में खातेवारी अधिकार घोषित


20/11/17
रजिस्ट्रार अपील प्राधिकारी
ओगाणगर (राज.)

करवाने का अधिकारी है। उपरोक्त न्याय सिद्धांतों के अतिरिक्त अभिनाथक अपीलाट द्वारा अपने कथनों के समर्थन में विधायिका द्वारा पारित कानूनों का हवाला देते हुए जाहिर किया कि राज.काश्त.अधि. की धारा 214(3) द्वारा भारतीय मियाद अधिनियम 1908 जिसमें मियाद अधिनियम 1963 को Adopt किया है। अतः मियाद अधिनियम के तमाम प्रावधान राज.काश्त.अधि. पर लागू होकर मियाद अधिनियम में निहित प्रतिकूल कब्जे के आधार पर अपीलाट खातेदारी अधिकारों को घोषित कराने का पात्र है जैसाकि यह Settled Law है कि राज.काश्त.अधि. 1955 की धारा 88 के तहत Adverse possession के आधार पर खातेदारी अधिकारों की घोषणा की जा सकती है। अतः अपीलाट को खातेदार काश्तकार घोषित किया जावे।

प्रतिकूल कब्जे के सम्बन्ध में उभयपक्ष द्वारा प्रस्तुत न्याय सिद्धांतों में प्रतिकूल कब्जे के आधार पर खातेदारी अधिकार देने व न देने के दोनों ही मत प्रतिपादित हैं। अतः राज.काश्त.अधि. के अन्तर्गत प्रतिकूल कब्जे के आधार पर घोषणात्मक दावे के आधार पर खातेदारी अधिकार दिये जाने पर विधि विशेषज्ञों के मत का भी अध्ययन किया जिसके अनुसार राजस्थान काश्तकारी अधिनियम में प्रतिकूल कब्जे के आधार पर specifically खातेदारी अधिकार दिये जाने का प्रावधान नहीं है। परन्तु अधिनियम का कोई प्रावधान प्रतिकूल कब्जे के आधार पर खातेदारी अधिकार देने से मना (Forbids) भी नहीं करता। ऐसी स्थिति में प्रत्येक प्रकरण की merits व न्यायिक निर्णयों के precedents निर्णय करने में सहायक हो सकते हैं साथ ही राजस्थान काश्तकारी अधिनियम में Adverse possession एवं खातेदारी दावों के घोषणा के सम्बन्ध में विभिन्न धाराओं में सन्दर्भ उपलब्ध है। अतः उनका समग्र अध्ययन ही प्रकरण की merits के अनुसार अच्छी quality का निर्णय किया जा सकता है।

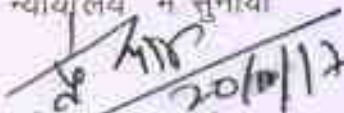
उभयपक्ष अभिनाथकगण द्वारा प्रस्तुत न्याय सिद्धांत एवं लिखित बहस का गहन से अध्ययन करने तथा पत्रावली पर उपलब्ध रिकार्ड प्रकरण की merits तथ्य विधि का विवेचन करने के पश्चात यह न्यायालय इस निष्कर्ष पर पहुंचता है कि प्रतिकूल कब्जे के प्रावधान मियाद अधिनियम का विधान है तथा भारतीय मियाद अधिनियम 1908 जिसमें पठित मियाद अधिनियम 1963 को राज.काश्त.अधि. की धारा 314(3) द्वारा अंगीकार किया है। तथ्यात्मक रूप से यह निर्विवाद साबित


20/11/17
राजस्थान अपीलाट प्राधिकारी
श्रीवाहनगर (राज.)



हे कि विवादित आराजी का कब्जा पिछले 30 वर्षों से अपीलान्ट के पास है जिसे रेष्यों ने deny नहीं किया है तथा अपीलान्ट के cross objection में भी यह confessed है तथा उभयपक्ष के न्याय सिद्धांत अपनी-अपनी जगह सन्दर्भित है। अतः यह Legal dilemma है कि राजस्थान कारतकारी अधिनियम में Adverse possession के आधार पर खातेदारी अधिकार दिये जाने के specific प्रावधान नहीं है। अतः अगर अपीलान्ट की अपील स्वीकार नहीं होती तब भी विधि अनुसार रेष्यों के खातेदारी अधिकार राज.कारत.अधि. की धारा 63IV के प्रावधानुसार Extinguish हो चुके हैं तथा राज.कारत.अधि. की धारा 183 के मियाद बिन्दु के निहित प्रावधानुसार रेष्यों का कब्जा वापिसी का कानूनी अधिकार विधि द्वारा वर्जित है। अतः खातेदारी अधिकार inmedio रह नहीं सकते तथा मियाद अधि. 1963 के पार्ट- IV के प्रावधानुसार अपीलान्ट को " Acquisition of ownership by possession" का संरक्षण प्राप्त है तथा राज.कारत.अधि. की विविध धाराओं यथा 15, 19, 42, 53, 88, 183 के consolidate अध्ययन से Adverse possession के आधार पर खातेदारी अधिकार दिया जाना विवेचित है। अतः विवादित आराजी किसके पास है किसके पास रह सकती है। तुलनात्मक सुविधा का सन्तुलन अपीलान्ट या रेष्यों में से किसके पक्ष में है जो निःसन्देह अपीलान्ट के पक्ष में होने से अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाती है। अधी. न्यायालय द्वारा विवेचित तनकी सं. 1 के अनुरूप अधी. न्यायालय का निर्णय दिनांक 18.01.2017 अपास्त कर अपीलान्ट को विवादित भूमि बक 7 डी बड़ी के खाता सं. 51/50 मु.न. 25 के कि. न. 2 से 15 की 3.062 हे० तथा मु.न. 26 के कि.न. 1/1 की 0.128 हे० व 67/9 का 0.076 है. कुल 3.264 हे० का खातेदार कारतकार घोषित किया जाता है।

निर्णय आज दिनांक 20.11.2017 को मेरे द्वारा खुले न्यायालय में सुनाया गया।


(प्रसादराम परमार)
राजस्व अपील प्राधिकारी
श्रीगंगानगर



डिक्री व सीगे अपील

(ओ.41 कल 35, जाका दिवानी)

न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, श्रीगंगानगर

इजलास श्री प्रेमराम परमार, आर.ए.एस., राजस्व अपील प्राधिकारी,

1. जगदीश चन्द पुत्र सुलतानराम जाति जाट निवासी भदरा तहसील व जिला श्रीगंगानगर ।
2. विनोद कुमार पुत्र सुलतानराम जाति जाट निवासी भदरा तहसील व जिला श्रीगंगानगर ।

— अपीलार्थीगण

बनाम

1. मन्नीदेवी पत्नी रणजीतसिंह पुत्र हरचन्द जाति जाट निवासी ख्योवाली तहसील सिरसा हरियाणा ।
2. कुलवंतसिंह } पिसरान रणजीत जाति जाट निवासी ख्योवाली
3. हनुमान } तहसील सिरसा हरियाणा ।
4. नरेश कुमार }
5. विद्यादेवी पत्नी आत्माराम पुत्र हरचन्द जाति जाट निवासी ख्योवाली तहसील सिरसा हरियाणा ।
6. राजेन्द्र कुमार पुत्र आत्माराम पुत्र हरचन्द जाति जाट निवासी ख्योवाली तहसील सिरसा हरियाणा ।
7. कृष्णादेवी पुत्री आत्माराम पुत्र हरचन्द जाति जाट निवासी ख्योवाली तहसील सिरसा हरियाणा ।
8. स्टेट आफ राजस्थान सरकार जारिये तहसीलदार श्रीगंगानगर ।

— रेषपोडेन्ट

अपील संख्या 08/2017 व नाराजगी डिक्री अदालत सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक) श्रीगंगानगर मुकाम घडसाना मुख्य 16 माह 01 सन् 2017

दावा बाबत

यह अपील व तारीख 20 माह 11 सन् 2017 रुबरु मुझ हाजरी श्री ओमप्रकाश बतरा अभिभाषक मिनजानिव अपीलट व दिनेश छाबडा अभिभाषक रेषपो एवं इकबालसिंह सिद्धू राजकीय अधिवक्ता समाजत के लिए पेश होकर

राजस्व अपील प्राधिकारी
श्रीगंगानगर (राज.)

हुवन हुआ कि अपील अपीलांत स्वीकार की जाती है। अधी. न्यायालय द्वारा विवेचित तनकी सं. 1 के अनुरूप अधी. न्यायालय का निर्णय दिनांक 16.01.2017 अपास्त कर अपीलांत को विवादित मूमि चक 7 डी बड़ी के खाता सं. 51/50 मु.न. 25 के कि.न. 2 से 15 की 3.062 हे० तथा मु.न. 26 के कि.न. 1/1 की 0.126 हे० व 67/9 का 0.076 हे० कुल 3.264 हे० का खातेदार कास्तकार घोषित किया जाता है।

(खर्चा अपील हाजा का इस्व तफसील जेर तादादी मुबलिंग - X -) रूपये - X -
... अदा करें, खर्चा मुकदमा मातहत का - X - अदा करें।

बसक्त मेरे हस्ताक्षर व मुहर अदालत आज तारीख 20.11.2017 जारी किया गया।



[Handwritten Signature]
राजस्व अपील प्राधिकारी
श्रीगंगानगर